

क्षेत्र में होंगे।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने ट्रेक्टर कारखाने के लिये अब तक किसी वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है।

मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

2158. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान मध्य प्रदेश में बिछाई गई नई रेलवे लाइनों का व्यौरा क्या है तथा उनकी लम्बाई

कितनी है ; और

(ख) राज्य में वर्ष 1971-72 में बिछाई जाने वाली नई रेलवे लाइनों का और छोटी मीटर गेज लाइनों से बड़ी लाइनों में बदली जाने वाली लाइनों का व्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतिया) : (क) रेलवे विकास का कार्यक्रम किसी राज्यवार या क्षेत्रवार आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास की दृष्टि से तैयार किया जाता है। फिर भी, ओवरा-सिगरौली लाइन, जिसकी कुल लम्बाई 57.56 कि० मी० है, का 19.89 कि० मी० भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसे 30-4-1971 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित लाइनें बनायी जा रही हैं :

विवरण	आमान	लम्बाई (कि० मी० में)	पूरी होने की निर्धारित तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1. मोरवा (सिगरौली) कटनी	बड़ी लाइन	254.00	मार्च, 1972
2. गुना-मक्सी	बड़ी लाइन	192.22	जुलाई, 1973

(ख) 1971-72 में राज्य में कोई नयी लाइन बनाने या आमान परिवर्तन का काम शुरू करने का विचार नहीं है। फिर भी नयी लाइनों के सर्वेक्षण आमान परिवर्तन का जो काम चालू प्रस्तावित है, उन पर काम शुरू करने का कार्यक्रम इस प्रकार है :

I. चालू काम :

(i) दिल्ली राजहरा—दातिवाड़ा/जगदल

पुर।

रेलसम्पर्क—1965-66 के अध्ययन दल द्वारा दी गयी रिपोर्ट की व्यवहारिकता और लागत का पुनर्मूल्यांकन।

(ii) रायपुर—धमतारी छोटी लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव-यातायात सर्वेक्षण।

## II. 1971-72 में किया जाने वाला प्रस्तावित सर्वेक्षण

सतपुड़ा छोटी लाइन रेल प्रणाली के उत्तरी खंड का बड़ी लाइन में बदलाव-यातायात सर्वेक्षण।

### Legal Aid to Lower Income Group People

2159. SHRI BHOGENDRA JHA :  
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that seeking legal justice is a costly affair under the present conditions, particularly for lower income group people ;

(b) whether Government propose to ensure exemption from court fees or stamp duties, free provision of lawyers and certified copies etc. to all those owing less than 2½ acres of irrigated and 5 acres of non-irrigated land and to all those families having an annual income of less than Rs. 1500; and

(c) if so, main feature of the scheme in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY):  
(a) Government, are aware that in some cases difficulty is experienced by lower income group people while seeking justice on account of paucity of funds.

(b) and (c). There is no such proposal under the consideration of the Central Government. However, some provisions have been made in the Advocates (Amendment) Bill, 1970 with a view to providing legal aid to the poor through the agency of the Bar Council of India and the State Bar Councils.

## Setting up of New Unit by H.M.T.

2160. SHRI DHARAMRAO AFZAL-PURKAR : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Hindustan Machine Tools Ltd., (Bangalore) has planned to set up five more units by 1973-74;

(b) if so, the particulars of the units and likely investment therein ; and

(c) the number of persons likely to be employed thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD):  
(a) and (b). Hindustan Machine Tools contemplate six new projects during the IV Plan period. The names, location of the projects and the estimated investment thereon are as under :

Name of the Project & location	Investment (Rs. lakhs)
1. Bangalore Watch Factory expansion	366
2. Srinagar Watch Factory	425
3. Tractor Project, Pinjore	491
4. Printing Machinery Project, Kalamassery	330
5. Metal forming presses, Hyderabad	330
6. Plastic Injection Moulding Machine Project, Bangalore, (non-plan)	105